

आजुबारा

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक
हर खबर पर पैनी नज़र

वर्ष : 11 अंक : 09

लखनऊ, रविवार 07 जून से 13 जून, 2020 तक

पृष्ठ—8

मूल्य : एक रूपया

सीएम योगी ने किया २८ विद्युत उपकेंद्रों का शिलान्यास

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर ३१३५ करोड़ की लागत से बने २८ विद्युत उप केंद्रों का शिलान्यास तथा लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में भी पिछले ढाई महीनों से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने में पावर कर्पोरेशन ने प्रदेश के अंदर अच्छी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि 'पावर फॉर ऑल' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप प्रत्येक घर तक आने वाले समय में २४ घंटे की बिजली आपूर्ति कर सकें इसका निरंतर प्रयास रहा है। उन्होंने कहा कि इस संकल्प को और भी सुदृढ़ करने की दिशा में आज ३१३५ करोड़

से निर्मित २८ ट्रांसमिशन उपकेंद्रों के शिलान्यास और लोकार्पण की यह कड़ी जोड़ी जा रही है। योगी ने



कहा कि आज प्रदेश सरकार ने १,८८९.७८ करोड़ की लागत से जिन परियोजनाओं को पूरा किया है, उनका लोकार्पण कार्यक्रम सम्पन्न हो रहा है। १,२५३.५६ करोड़ की लागत से नई योजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम सम्पन्न हो रहा है। यह

जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के साथ ही पावर फॉर ऑल के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उठाए गए कदमों की एक नई श्रृंखला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट के समय में भी उत्तर प्रदेश पावर कर्पोरेशन उत्तर प्रदेश के ३२ करोड़ लोगों के साथ खड़ा है। मंत्री श्रीकांत शर्मा तथा रमाशंकर सिंह पटेल भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास प्रदेश में हर जगह पर २४ घंटे विद्युत आपूर्ति का है। हम अपने इस अभियान में सफल भी होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण में लॉकडाउन के बाद भी हमारी सरकार का लक्ष्य विकास की गति को बरकरार रखने का है।

बाबरी मस्जिद मामले में आरोपी प्रकाश शर्मा का बयान दर्ज, पहले दो का दर्ज हो चुका है बयान

लखनऊ। अयोध्या प्रकरण पर सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद ढहाये जाने के मामले में आरोपी प्रकाश शर्मा का सीआरपीसी की धारा-३१३ के तहत शनिवार को बयान दर्ज किया। शर्मा तीसरे आरोपी है, जिनका बयान अदालत ने दर्ज किया है। इससे पहले अदालत विजय बहादुर सिंह और गांधी यादव के बयान दर्ज कर चुकी है। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालेंष आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी रितंभरा, विनय कटियार और राम विलास वेदांती सहित ३२ में से २६ आरोपियों के बयान सीआरपीसी की धारा-३१३ के तहत

दर्ज होने बाकी हैं। अदालत आठ जून को अन्य आरोपियों के बयान दर्ज करना जारी रखेगी। आरोपी प्रकाश शर्मा शनिवार को अपने वकील के साथ विशेष न्यायाधीश



एस.के. यादव के समक्ष पेश हुए। हर आरोपी को बयान दर्ज कराने में लगभग एक दिन का समय लग रहा है क्योंकि अदालत द्वारा तैयार किए गए करीब एक हजार सवाल प्रत्येक आरोपी से पूछे जा रहे हैं। अदालत ने दोहराया कि आरोपी बचाव के साक्ष्य, यदि कोई हैं, तो लिखित में जमा कराएँ। कुल ३२ आरोपी हैं, जिन पर इस प्रकरण में मुकदमा चल रहा है। शनिवार को केवल प्रकाश शर्मा अदालत के समक्ष पेश हुए। अदालत ने २८ आरोपियों को एक दिन के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी। पूर्व प्रधानमंत्री लालेंष आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती को अदालत ने २०१७ में ही अगले आदेश तक व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी थी।

ईडी अधिकारी कोविड-19 से संक्रमित, मुख्यालय सील

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय के पांच कर्मचारियों के कोविड-१९ से संक्रमित पाए जाने के बाद जांच एजेंसी के मुख्यालय को सोमवार तक ४८ घंटों के लिए सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि संक्रमित कर्मचारियों में विशेष निदेशक रैंक का एक अधिकारी भी शामिल है। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पांच में से दो अनुबंध पर काम करने वाले कर्मचारी हैं। खान मार्केट में लोकनायक भवन

की अन्य मंजिलों से कोविड-१९ के मामले सामने आने के मद्देनजर एजेंसी ने अपने मुख्यालय में विभागवार जांच कराई जिसमें ये कर्मचारी संक्रमित पाए गए। लोकनायक भवन में ही ईडी का कार्यालय स्थित है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित मिले ईडी के सभी कर्मचारियों में इस बीमारी के लक्षण नजर नहीं आ रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक, जिन कर्मचारियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है उनमें विशेष

निदेशक रैंक के एक अधिकारी और एक जांच अधिकारी शामिल हैं। सभी को इलाज के लिए पृथक-वास केंद्रों में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि संक्रमित कर्मचारियों के संपर्क में आए लोगों को पृथक-वास में रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रक्रिया के अनुसार, एजेंसी के मुख्यालय को ४८ घंटों के लिए सील कर दिया गया है और वह सोमवार से काम करना शुरू करेगा। उन्होंने बताया कि जांच में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद से ये

कर्मचारी दफ्तर नहीं आ रहे थे। उन्होंने बताया कि कोविड-१९ के प्रसार को रोकने के क्रम में, ईडी मुख्यालय और सभी दस्तावेजों को हफ्ते में दो बार संक्रमणमुक्त करने के संबंध में एक प्रोटोकल निष्पत्ति किया गया। साथ ही बताया कि डाक को अधिकारियों और एजेंसी के अन्य स्टाफ को सौंपने से पहले संक्रमणमुक्त किया जाता है। पिछले महीने भी ईडी का एक कर्मचारी कोविड-१९ की जांच में संक्रमित पाया गया था।

प्रियंका गांधी ने की अजय कुमार लल्लू की रिहाई की मांग, यूपी सरकार पर लगाया दमन का आरोप

लखनऊ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्ढा ने पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई की मांग करते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि लोगों की



सेवा करने के कारण उन्हें जेल में डाला गया है। गौरतलब है कि बस प्रकरण के मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लल्लू को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं। प्रियंका ने ट्वीट किया, "गांधीजी ने हमें सिखाया कि दमन करने वाले आपको अच्छे काम करने से रोकेंगे।

आप सत्य के आग्रह के साथ अपने कर्म पर डटे रहिए।" कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने आरोप लगाया, "उप्र कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू जी को सेवा करने के लिए जेल में डाला गया। सेवा सत्याग्रह के जरिए हम इस दमन का विरोध कर रहे हैं।" कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने शनिवार को पार्टी के 'सेवा सत्याग्रह' अभियान के तहत सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से लल्लू की रिहाई की मांग की। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, "क्या जन सेवा अब पाप है? क्या मजदूरों के साथ खड़े होना अपराध है? क्या उन्हें घर पहुंचाना गुनाह है? अगर नहीं, तो अजय लल्लू को तानाशाही भाजपा सरकार के द्वारा जेल की सलाखों के पीछे क्यों डाला गया है? फौरन रिहा करें।

२५ जिलों में नौकरी करने वाली शिक्षिका गिरफ्तार

कासगंज। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फर्जीवाड़ा करने वाली शिक्षिका अनामिका शुक्ला को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह २५ जिलों में फर्जी तरीके से नौकरी कर रही थी। कोतवाली प्रभारी रिपुदमन सिंह ने बताया कि शिक्षिका अनामिका शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। ज्ञात हो कि प्रदेश में २५ जिलों में फर्जी तरीके से नौकरी करने के मामले में सुर्खियों में आई शिक्षिका अनामिका शुक्ला को कासगंज पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। कासगंज के बेसिक शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में उसने अपने साथी के हाथ से त्यागपत्र भेजा था, लेकिन उसके साथी को दफ्तर में बैठा लिया गया। इसके बाद बीएसए ने अपने ऑफिस के कर्मचारियों को भेज कर

उसे सड़क से पकड़वाया और थाना सोरो पुलिस को सौंपा है। अनामिका शुक्ला कासगंज के कस्तूरबा विद्यालय फरीदपुर में विज्ञान की शिक्षिका के रूप में पूर्णकालिक रूप



से सेवाएं दे रही थीं। बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर जिले में अनामिका शुक्ला नाम की शिक्षिका की तलाश की गई तो कस्तूरबा विद्यालय में यह शिक्षिका पाई गई। शुक्रवार को बीएसए (बेसिक शिक्षा अधिकारी)

ने शिक्षिका के वेतन आहरण पर रोक लगाते हुए नोटिस जारी किया था। बीएसए अंजलि अग्रवाल का कहना है मार्च में लॉकडाउन में शिक्षिका अनामिका शुक्ला अपने घर गई थी, दूसरे के अभिलेख प्रयोग करने के मामले में उसे नोटिस भेज कर जांच कमेटी का गठन किया गया है। मंडल स्तर पर इस मामले की जांच एडी बेसिक अलीगढ़ कर रहे हैं। अनामिका कासगंज में भी कस्तूरबा गांधी स्कूल में फुल टाइम शिक्षिका के रूप में काम कर रही थी। कासगंज में काम करने वाली अनामिका शुक्ला ने अभिलेखों में अपना पता फर्रुखाबाद के लखनपुर का दिखाया है। गुरुवार को शासन से पत्र आने के बाद में विभाग ने केजीबी में कार्य करने वाली शिक्षिका अनामिका को नोटिस जारी किया था।

सम्पादकीय

यूबीआई की धारणा पर आंशिक अमल

पिछले लोक सभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने न्यूनतम आय गारंटी योजना (न्याय) लागू करने का वादा किया था। इसके तहत आमदनी के लिहाज से निचले हिस्से की आधी आबादी को हर महीने ६००० हजार रुपये बिना शर्त दिए जाते। अब कोरोना संकट के बीच स्पेन की सरकार ने ऐसी योजना लागू करने की दिशा में कदम उठा लिया है। वहां की संसद ने पिछले हफ्ते इसके लिए विधेयक पास कर दिया। जल्द ही इस पर अमल शुरू हो जाएगा। कांग्रेस की न्याय और स्पेन की न्यूनतम आय गारंटी योजना काफी कुछ मिलती-जुलती है। जानकारों के मुताबिक ये ये योजनाएं असल में यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई) की धारणा पर आंशिक अमल हैं। इस धारणा की चर्चा पिछले अनेक वर्षों से चल रही है और कुछ देशों में इस पर प्रयोग भी हुए हैं। २०१६-१७ में नरेंद्र मोदी सरकार के तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रह्मण्यम अपनी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा था कि भारत में यूबीआई को लागू करने का वक्त आ गया है। तब बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन इस धारणा पर चर्चा जरूर हुई। अब कोरोना की मार झेल रहे अनेक देशों में इस पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इस संदर्भ में उन देशों के अनुभवों पर गौर किया जा रहा है, जहां इस संबंध में प्रयोग हुए। मसलन, फिनलैंड। फिनलैंड ने इस प्रयोग को कुछ समय के बाद बंद कर दिया। वहां ऐसे बहुत से लोग हैं, जो इसे एक नाकाम आइडिया करार देते हैं। इसे फेल कहने वालों की राय है कि इसका रोजगार सृजन में बहुत ही कम योगदान रहा है। मगर इसे सफल मानने वालों की भी कमी नहीं है। प्रयोग का क्या अनुभव रहा इसका अध्ययन करने के लिए जनवरी २०१७ से दिसंबर २०१९ तक के आंकड़े जुटाए गए। शोध में साफ पता चला कि हर महीने ५६० यूरो पाने वाले लोगों में असुरक्षा और तनाव का स्तर बहुत कम था। कुल मिलाकर लोगों के जीवन में एक तरह की खुशहाली आई। यानी जिन्हें बेसिक इनकम मिल रही थी वे मानसिक रूप से बेहतर महसूस कर रहे थे। कई जानकारों का कहना है कि जब खुशहाली रहती है, तो लोगों के रोजगार पाने की संभावना भी बढ़ जाती है। नौकरी देने वाले उन्हें कार्य करने में सक्षम व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। इसलिए इस योजना के समर्थकों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पर बड़े पैमाने पर अमल होगा।

शिक्षिका ने २५ स्कूलों से कैसे कमाए एक करोड़ रुपये

लखनऊ। एक शिक्षिका अनामिका शुक्ला की २५ स्कूलों में महीनों से हाजिरी लग रही थी। एक डिजिटल डेटाबेस होने के बावजूद एक करोड़ रुपये का वेतन निकालने में वह सफल रहीं। यह असंभव सा लग सकता है लेकिन सच है। वह कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) में कार्यरत पूर्णकालिक विज्ञान शिक्षिका थीं और अंबेडकर नगर, बागपत, अलीगढ़, सहारनपुर और प्रयागराज जैसे जिलों के कई स्कूलों में एक साथ काम कर रही थीं। मामला तब सामने आया जब शिक्षकों का एक डेटाबेस बनाया जा रहा था। मानव सेवा पोर्टल पर शिक्षकों के डिजिटल डेटाबेस में शिक्षकों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड, जुड़ने और पदोन्नति की तारीख की आवश्यकता होती है। एक बार रिकॉर्ड अपलोड होने के बाद, यह पाया गया कि अनामिका शुक्ला, एक ही व्यक्तिगत विवरण के साथ २५ स्कूलों में सूचीबद्ध थीं। स्कूल शिक्षा के महानिदेशक, विजय किरण आनंद ने कहा कि इस शिक्षक के बारे में तथ्यों का पता लगाने के लिए एक जांच चल

रही है। शिक्षिका संपर्क में नहीं है। उन्होंने कहा, "यह आश्चर्यजनक है कि शिक्षिका अनामिका शुक्ला उग्र के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति की वास्तविक समय पर निगरानी किए जाने के बावजूद ऐसा कर पाई।" मार्च में इस शिक्षिका के बारे में शिकायत प्राप्त करने वाले एक अधिकारी ने कहा, "एक शिक्षक अपनी उपस्थिति को कई जगह कैसे चिह्नित कर सकता है, जबकि उन्हें प्रेरणा पोर्टल पर अनलाइन उपस्थिति दर्ज करनी होती है?" सभी स्कूलों में रिकॉर्ड के अनुसार, शुक्ला एक साल से अधिक समय तक इन स्कूलों के रोल पर थीं। केजीबीवी कमजोर वर्गों की लड़कियों के लिए चलाया जाने वाला एक आवासीय विद्यालय है, जहां शिक्षकों को अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है। उन्हें प्रति माह लगभग ३०,००० रुपये का भुगतान किया जाता है। जिले के प्रत्येक ब्लक में एक कस्तूरबा गांधी स्कूल है। अनामिका ने इन स्कूलों से वेतन के रूप में फरवरी २०२० तक (१३ महीनों में) एक करोड़ रुपये लिए

अकुशल को प्रशिक्षण और हुनरमंदों को रोजगार देगी योगी सरकार

राकेश पाण्डेय "निश्चल"
लखनऊ। कोरोना संकट के कारण दूसरे प्रदेशों में रह रहे श्रमिकों और कामगारों की वापसी उग्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर अब तक करीब ३२ लाख श्रमिकों की सुरक्षित और ससम्मान वापसी हो चुकी है। अब यह सिलसिला थमता सा नजर आ रहा है। अब सरकार के सामने दूसरी सबसे बड़ी चुनौती वापस आने वाले श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना है। सरकार ने इस समस्या के हल की भी मुकम्मल कार्ययोजना तैयार कर ली है। जो हुनरमंद हैं उनको सरकार रोजगार देगी और जो अकुशल या अर्द्धकुशल हैं, प्रशिक्षण के जरिए उनका हुनर निखारेगी। इसका इन श्रमिकों को दीर्घकालिक लाभ होगा। ऐसे श्रमिक जिनको किसी खास प्रशिक्षण की जरूरत होगी, उनको कौशल विकास मिशन के जरिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि मिशन में इसकी व्यवस्था नहीं है तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग(एमएसएमई) विभाग द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों (एक जिला एक उत्पाद, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों) के तहत उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि सरकार द्वारा संचालित किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबंधित के हुनर के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है तो उपायुक्त उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन

ब्यूरो कौशल मिशन की ओर से जारी अप्रेंटिस कार्यक्रमों के तहत उसी उद्योग में उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा। यदि किसी भी योजना में प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है तो इसकी व्यवस्था सरकार करेगी। ऐसे प्रशिक्षण के लिए एक प्रस्ताव बनाकर शासन



को भेजना होगा। हर श्रमिक को बीमा की सुरक्षा भी देने की योजना है। अगर श्रमिक किसी और जिले में काम पर जाता है तो उसकी आवसीय व्यवस्था भी सरकार करेगी। मालूम हो कि दूसरे प्रदेशों से अब तक करीब ३० लाख से अधिक कामगार एवं श्रमिक अब तक वापस आ चुके हैं। इनमें से करीब २४ लाख के रिकॉर्ड की मैपिंग हो चुकी है। इसमें अकेले २२ लाख से अधिक संख्या निर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों की है। बाकी लौटने वाले श्रमिक दूसरे प्रदेशों में रंग-रोगन, बर्दई, झाड़वर, दर्जी, कुक, प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, नाई, ब्यूटी पार्लर, धोबी, माली हाउस कीपिंग, आटो

रिपेयरिंग और सेल्स एंड मार्केटिंग आदि का काम करते रहे हैं। इनमें से करीब १७ लाख संख्या अकुशल श्रमिकों की है। मुख्यमंत्री बार-बार दूसरे प्रदेशों से आने वाले हर श्रमिक को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने और जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण के जरिए उनका हुनर निखारने के प्रति प्रतिबद्धता जता चुके हैं। इस पर काम भी शुरू हो चुका है। २६ मई को मुख्यमंत्री की पहल पर उनके आवास पर आयोजित कार्यक्रम में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लघु भारती, नारडको (नेशनल रीयल इस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल) और फिक्की (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री) से ११ लाख श्रमिकों को रोजगार देने का समझौता हुआ था। आगे भी इस तरह के और एमओयू होंगे। प्रमुख सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल ने बताया, "सभी कामगारों-श्रमिकों को प्रदेश में ही रोजगार के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने की योगी सरकार की तैयारी है। इन सबको कामगार-श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) कल्याण आयोग के जरिए उनकी दक्षता के अनुसार स्थानीय स्तर पर काम दिया जाएगा।"

विश्व पर्यावरण दिवस पर सड़क परिवहन निगम ने की बड़ी मुहिम की तैयारी

लखनऊ। विश्व पर्यावरण दिवस पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने एक बड़ी मुहिम की तैयारी की है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण बचाने को लेकर और प्रदूषण मुक्त बस संचालन करने के लिए रोडवेज ने बड़ी पहल की है। प्रदेश की हवा को स्वच्छ रखने के लिए परिवहन निगम अपने बस बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करेगा और सीएनजी बसों के बेड़े को भी मजबूत करेगा। डीजल बसों के संचालन को कम करने की भी तैयारी कर ली गई है। रोडवेज के अधिकारियों के अनुसार नई डीजल बसें यूरो सिक्स की होंगी, जिनसे हानिकारक तत्वों का उत्सर्जन कम होगा। पर्यावरण को रोडवेज बसों से निकलने वाले जहरीले धुंए से बचाने के लिए जहां स्मोक मीटर की लगाए जाने की तैयारी है वहीं बेड़े में नई सीएनजी बसों को शामिल किया जाएगा। अभी सिर्फ लखनऊ में उपनगरीय डिपो में ही करीब १४ सीएनजी बसें शामिल हैं। इनका संचालन चारबाग से किया जाता है। इसके अलावा नोएडा और दिल्ली के क्षेत्रों में भी सफर के लिए सीएनजी बसों का संचालन हो रहा है। वहां इनकी संख्या १०० से अधिक है। लखनऊ की हवा को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए यहां से आस-पास

अन्य जिलों के लिए भी सीएनजी बसों का संचालन शुरू किए जाने की तैयारी है। इनमें कानपुर, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी को शामिल किए जा सकते हैं। १०० नई सीएनजी बसों को लाए जाने की तैयारी चल रही है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का ट्रायल हो चुका है। इन बसों को उन्हीं क्षेत्रों में चलाया जाएगा जहां पर प्रदूषण की समस्या अधिक है। तकरीबन १०० नई बसों को चलाया जाना है। इसके लिए भी प्लानिंग की जा रही है। बता दें कि गुरुवार को ही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और रोडवेज की बड़ी सराहना की है। परिवहन निगम प्रदेशवासियों को सुगम सुरक्षित यात्रा कराने के साथ ही प्रदूषण मुक्त संचालन को लेकर कसरत कर रही है। उत्तर प्रदेश से चलने वाली सभी रोडवेज बसों को प्रदूषण मुक्त किया जाएगा। रोडवेज बसों से निकलने वाले धुंए की रोजाना जांच कराई जाती है। बसों में प्लास्टिक की बोतलों का प्रयोग बंद किया जा चुका है। वहीं सीएनजी बसों का बेड़ा बढ़ाए जाने और इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की तैयारी कर ली गई है। डॉ. राजशेखर, प्रबंध निदेशक, यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम

अयोध्या मामले में ३२ आरोपियों की अदालत में पेशी होगी दर्ज होंगे बयान

लखनऊ। करीब दो दशकों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराये जाने के ३२ आरोपियों की गुरुवार से अदालत में पेशी होगी जहां उनके बयान रिकार्ड किये जायेंगे। छह दिसम्बर १९६२ को विवादित ढांचा गिराया गया था। इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालेश आडवाणी, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और उनके वकीलों को न्यायालय में पेश होने के बारे में सूचित कर दिया गया है। अदालत में सभी अभियुक्तों के बयान सीआरपीसी की धारा ३१३ के तहत रिकार्ड किये जायेंगे। अदालत उनके खिलाफ पेश के किये गये साक्ष्य प्रस्तुत करेगी जिनका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। पहले दिन गुरुवार को पूर्व सांसद राम विलास वेदाती, विजय बहादुर और संतोष

दुबे अयोध्या मामले की विशेष अदालत के न्यायाधीश एसके यादव के सम्मुख पेश होंगे। इसके अलावा भाजपा सांसद बृज भूषण सरन सिंह, लालू सिंह, साक्षी

ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, साधु रितम्भरा, महंत नृत्य गोपाल दास, महंत धर्मदास, आरएन श्रीवास्तव, पवन कुमार पांडे और सतीश प्रधान भी शामिल हैं।



उच्चतम न्यायालय के सख्त निर्देश के बाद न्यायालय ने ३२ अभियुक्तों के बयान रिकार्ड करने के प्रयास शुरू किये हैं और अगर जरूरत पड़ी तो बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये भी रिकार्ड किये जायेंगे। इससे पहले उच्चतम

न्यायालय ने अयोध्या मामले की विशेष अदालत से १८ अप्रैल तक ट्रायल प्रक्रिया पूरा करने को कहा था लेकिन लाकडाउन के कारण इस समय सीमा को बढ़ाना पड़ा था। विशेष न्यायाधीश की अपील पर उच्चतम न्यायालय ने ट्रायल की समयावधि को बढ़ा कर ३१ अगस्त कर दी थी।

महाराज और विनय कटियार के बयान भी रिकार्ड किये जायेंगे। पिछले महीने न्यायालय ने सीबीआई के गवाहों के बयान सुने थे। इनमें दो के बयान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये रिकार्ड किये गये थे। विवादित ढांचे को गिराये जाने के अभियुक्तों की सूची में विहिप नेता और रामजन्मभूमि तीर्थ

केंद्र और राज्य सरकार खिलाफ के १६७४ से भी बड़े आन्दोलन की जरूरत : रामगोविंद चौधरी

राकेश पाण्डेय "निश्चल" लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने देश में जयप्रकाश नारायण के १६७४ में शुरू किए गए आंदोलन की तरह एक वैसे ही आंदोलन की जरूरत बताई और कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार कोरोना के मुकाबले के नाम पर गरीबी को नहीं, मजदूरों, श्रमिकों, बेरोजगारों, किसानों और गरीबों को मिटा देने पर तुली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता रामगोविंद चौधरी ने यहां कहा कि सरकारें अपने अनियोजित और मनमाने फैसलों से आम आदमी को प्रतिदिन मौत के मुँह में ढकेल रही हैं। देश को आर्थिक तबाही के मोड़ पर पहुँचा दिया गया है। इसलिए इनके खिलाफ आज १६७४

से भी बड़े छात्र युवा आन्दोलन की जरूरत है। उन्होंने छात्रों और नवजवानों से आग्रह किया है कि वे पांच जून को सम्पूर्ण क्रांति दिवस



के अवसर लोकनायक जयप्रकाश नारायण को याद करें और मजदूर, श्रमिक, बेरोजगारों, किसानों और गरीबों की रक्षा के लिए लाकडाउन नियमों का पालन करते हुए १६७४ से भी बड़े आंदोलन की तैयारी करें। रामगोविंद चौधरी ने कहा है

कि देश और राज्य सरकारों की कारपोरेट समर्थक नीति के कारण देश पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, काला बाजारी और आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। किसान रो रहा था। अल्पसंख्यक और धर्मनिरपेक्ष लोग शासन के संरक्षण में भीड़ हिंसा का शिकार हो रहे थे। बैंक दिवालिया हो रहे थे। कोरोना को लेकर विदेशों से आने वाले देश में बिना जांच पड़ताल के चारों तरफ आ जा रहे थे और देश तथा राज्यों की कुछ सरकारें विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी के बाद भी ट्रम्प के स्वागत और मध्यप्रदेश कब्जा की राजनीति में लगी रहीं तो कुछ सरकारें अपने दलीय हितों में।

चिनहट में भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले अभियंताओं पर विजिलेंस का शिकंजा

लखनऊ। लेसा के सबसे कमाई वाले सर्किल दो और डिवीजन चिनहट में पूर्व की सरकार में तैनात अभियंताओं की विजिलेंस जांच हो रही है। हालांकि जांच तो काफी समय से हो रही है, लेकिन अब जांच में विजिलेंस कार्यालय की ओर से तेजी की बात कही जा रही है। विजिलेंस आफिसर जांच में तेजी लाते हुए कार्रवाई की बात कह रहे हैं। विजिलेंस कार्यालय सूत्रों के अनुसार पॉवर कार्पोरेशन से विजिलेंस ने सपा सरकार में तैनात अभियंताओं के नामों को दोबारा से मांगे गए हैं। इसके साथ ही उस समय तैनात अभियंताओं के संपत्तियों का भी ब्योरा मांगा गया है। विजिलेंस अधिकारियों के अनुसार पूर्व की सपा सरकार में चिनहट में अभियंताओं

द्वारा किए गए कारनामों की जांच तो पहले ही चल रही थी, लेकिन धीमे थी। अब जांच में तेजी लाए जाने के आदेश दिए गए हैं और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है।

जांच में तेजी ला दिया गया है, यहां पर हुए कारनामों में शामिल अभियंताओं और कर्मचारियों पर दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई की जाएगी। यहां पर तैनात आधा दर्जन से ज्यादा अभियंता और बाबू जांच में शामिल हैं। इसके साथ ही इनकी संपत्तियों की भी जांच की जाएगी। -कमल सक्सेना, डीजी विजिलेंस

बता दें कि लेसा का सबसे महत्वपूर्ण और कमाई वाला सर्किल दो और डिवीजन चिनहट को माना जाता है। यहां पर तैनाती के लिए अभियंताओं और कर्मचारियों द्वारा जमकर जुगाड़ और कोशिशें की जाती हैं। यहां पर

तैनाती के लिए प्रबंधन की तरफ से कई बार तो नियमों को दरकिनार कर दिया गया। जो सबसे अच्छा रिस्पंस दे सके उसकी तैनाती की जाती है। आपको बता दें कि चिनहट

डिवीजन लेसा का सबसे कमाई वाला डिवीजन माना जाता है। पूर्व की सरकार में तैनात अभियंताओं ने जमकर उपभोक्ताओं और डिवीजन का दोहन किया था। यहां पर अभियंताओं और कर्मचारियों द्वारा मिलकर कई बड़े

अस्पताल दौरे के बाद अब उग्र के मंत्री सुरेश खन्ना का होगा कोरोना टेस्ट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्त और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना की गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर जांच होगी। मंत्री ने सोमवार को मेरठ के लाला लाजपत राय मेमोरियल (एलएलआरएम) मेडिकल कलेज का दौरा किया था। इस दौरान वह तीन कोविड-१९ संक्रमण से ग्रस्त रोगियों के संपर्क में आ गए थे। वर्तमान में मंत्री ने खुद को पहले से ही क्वारंटाइन कर दिया है। तीनों मरीजों की कोरोना संक्रमण को लेकर पजिटिव जांच रिपोर्ट बुधवार को आई, जिसके बाद स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. राज कुमार ने कहा कि मंत्री कुछ मिनटों के लिए ही वार्ड में रहे थे और ऐसे में उनके संक्रमित होने की संभावना बेहद कम है। सीएमओ ने कहा, "जिस अवधि तक मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अन्य नेता उक्त रोगियों के निकट थे, वह बहुत अधिक नहीं थी। एक व्यक्ति तभी संक्रमण से गस्त हो सकता है, जब उसने मरीज के साथ कम से कम १५ मिनट का जोखिम भरा वक्त बिताया हो।" मंत्री सहित स्थानीय भाजपा

कार्यकर्ताओं ने भी कई मीडियाकर्मियों के साथ वार्ड का दौरा किया था। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अब कहा है कि तीनों संक्रमित रोगियों के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों की जांच अगले पांच दिनों तक की जाएगी। सीएमओ ने कहा, "यदि अगले पांच



दिनों में उनमें कोई लक्षण दिखाते हैं, तो मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार उनकी जांच होगी और उन्हें उपचार के लिए भेजा जाएगा।" खन्ना कोरोना परीक्षण से गुजरने वाले उत्तर प्रदेश के दूसरे मंत्री होंगे। इससे पहले मार्च में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने एक पार्टी में भाग लिया था, जहां वह बॉलीवुड गायिका कनिका कपूर के संपर्क में आ गए थे। कनिका बाद में कोविड-१९ से संक्रमित पाई गई थीं। इसके बाद मंत्री की जांच हुई। हालांकि, जांच में सिंह के संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन इस पर काफी विवाद हुआ था।

ट्रक और स्कॉर्पियो की भिड़ंत, ६ की मौत

प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के थाना क्षेत्र नवाबगंज के वाजिदपुर में शुक्रवार को ट्रक और स्कॉर्पियो की भिड़ंत में नौ लोगों की मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के पीआओ त्रिलोकी पांडेय ने बताया कि प्रतापगढ़ जनपद नवाबगंज थाना क्षेत्र के वाजिदपुर में ट्रक और स्कॉर्पियो की आमने-सामने की टक्कर हो गयी है, जिसमें ६ लोग मर गये हैं। इनके साथ के एक व्यक्ति को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए

अस्पताल भेजा गया है। ये सभी स्कॉर्पियो में सवार होकर राजस्थान से बिहार जा रहे थे। पुलिस के अनुसार यह लोग बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। शवों को स्कॉर्पियो को काटकर बाहर निकाला गया। पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। उधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं।

कारनामों कर दिए गए। बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया था। अभियंताओं और कर्मचारियों ने विभाग के सभी नियमों का दरकिनार कर हजारों की संख्या में लंबी दूरी, सोसाइटी, बिल्डरों और समितियों को अवैध तरीके से कनेक्शन जारी कर दिया। यहां पर एक बड़ी बिजली चोरी का खुलासा उस दौरान मुख्य अभियंता रहे आशुतोष कुमार ने खुलासा किया था। जिसके बाद से कई और मामले सामने आ गए। आशुतोष ने एक बड़ी बिजली चोरी पकड़ी थी, जिसमें उपभोक्ता ने आरोप लगाते हुए बयान दिया था कि अभियंताओं और कर्मचारियों उसने बिजली चोरी के लिए नौ लाख रुपये दिए थे। जिसकी जांच हुई तो एक अवर

अभियंता को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि इन सभी मामलों में कई बड़े अभियंताओं का हाथ रहा, जिन्हें दबा दिया गया। वहीं सिर्फ अवर अभियंता को सस्पेंड और अधिशासी अभियंता को वहां से हटाकर खानापूर्ति कर दी गई। हालांकि उसके बाद इस मामले का विजिलेंस को दे दिया गया। जिसके बाद विजिलेंस जांच शुरू कर दी गई। लेकिन शासन के दबाव विजिलेंस जांच भी धीमी हो गई। वहीं यहां पर हुए कारनामों में शामिल कुछ अभियंताओं ने अपनी तैनाती शक्तिभवन में करवाकर मामले का दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब कहीं और से दबाव बनने के बाद विजिलेंस जांच में तेजी ला दी गई है।

योगी ने ८६,७१,१८१ लाभार्थियों के खातों में १३०१.८४ करोड़ रुपये अनलाइन हस्तांतरित किए

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास से कोविड महामारी के दृष्टिगत वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन की एक किस्त और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत अतिरिक्त राहत राशि के रूप में ८६,७१,१८१ लाभार्थियों के खातों में १३०१.८४ करोड़ रुपये ऑनलाइन हस्तांतरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना से जब पूरी दुनिया जूझ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी लोगों की चिंता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले अप्रैल में सभी लाभार्थियों को दो महीने की एकमुश्त पेंशन जारी की गई थी। अब इन्हीं लाभार्थियों को फिर से एक मुश्त धनराशि जारी की गई है। उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक क्लिक से लाभार्थियों

के खाते में सीधे धनराशि पहुंच रही है। ऐसा पहले नहीं था। पहले शोषण था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी व्यवस्था की है कि दिल्ली व लखनऊ से जारी होने वाली धनराशि १०० फीसदी लाभार्थियों



के खाते में समय से पहुंच रही है। योगी ने कहा कि लाभार्थियों को बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। कोरोना संकट में बैंक में भीड़ न हो, इसके लिए पेंशन धारक बैंक की बजाए बैंकिंग करस्पॉन्डेंट से अपने गांव में ही राशि हासिल कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना संकट का दौर चल रहा है, ऐसे में लोग भीड़ न लगाएं और सतर्क रहें। संक्रमण

से बचने के लिए सावधानी बरतें। गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग घर से बिल्कुल न निकलें। इसके बावजूद अगर किसी को घर से बाहर भी निकलना पड़ रहा है तो मुंह और नाक को गमछे व मास्कर से कवर जरूर किया जाना चाहिए। सरकार हर व्यक्ति को १० रुपये में दो मास्क मुहैया करवा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत प्रति लाभार्थी को १००० रुपये की राहत और माह जून की पेंशन की किस्त की धनराशि हस्तांतरित की गई है। इसमें वृद्धावस्था पेंशन के ४६,८७,०५४ लाभार्थियों को ७४८.०६ करोड़ रुपये, निराश्रित महिला पेंशन के २६,०६,२१३ लाभार्थियों को ३६०.६३ करोड़ रुपये, दिव्यांग पेंशन के १०,६७,७८६ लाभार्थियों को १६०.१७ करोड़ रुपये और कुष्ठावस्था पेंशन के १०,७२८ लाभार्थियों को २.६८ करोड़ रुपये शामिल हैं।

चालान की मैन्युअल व्यवस्था बंद, १५ जून से गाड़ियों के केवल होंगे ई-चालान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में १५ जून से गाड़ियों के केवल ई-चालान किए जाएंगे। अब चालान की मैन्युअल व्यवस्था बंद हो जाएगी। प्रदेश के १० जिलों में योजना का सफल संचालन किए जाने के बाद यातायात निदेशालय ने यह फैसला किया। आईजी (यातायात) दीपक रतन ने बताया कि पहले चरण में १० जिलों में ई-चालान की व्यवस्था पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई थी। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद इसे अन्य जिलों में भी लागू किया गया था। जिस गाड़ी का ई-चालान किया जाता है उसका ई-चालान वाहन मालिक के मोबाइल पर एसएमएस से पहुंच जाता है। साथ ही डाक से ई-चालान की कापी भी भेजी जाती है। इन सभी १० जिलों में योजना के सफल संचालन के बाद प्रदेश के सभी जिलों में नागरिक

पुलिस, यातायात पुलिस एवं राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) द्वारा ई-चालान की कार्रवाई शुरू की गई। वाहन स्वामी को नए चालान की सूचना दिए जाने के



लिए डाकखर्च की धनराशि उपलब्ध न होने के कारण कुछ जिलों में २० प्रतिशत मैन्युअल-पेपर चालान किया जा रहा था। इसके बाद अब फैसला किया गया है कि १५ जून से पेपर चालान या मैन्युअल चालान पूरी तरह से बंद कर दिया जाए और नागरिक पुलिस, यातायात पुलिस व रेलवे पुलिस द्वारा केवल ई-चालान की कार्रवाई ही की जाए।

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में छह लोग कोर्ट में बयान दर्ज कराने पहुंचे

लखनऊ। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले की सुनवाई कर रही सीबीआई की विशेष अदालत के समक्ष भाजपा के पूर्व सांसद विनय कटियार का बयान दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। गुरुवार को

अभियोजन की समस्त कार्यवाही समाप्त कर ली है। दरअसल अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही तो ६ मार्च को ही समाप्त हो गयी थी। कोर्ट ने अभियुक्तों को धारा ३१३ के तहत बयान के लिए बुलाना



मामले की सुनवाई के पूर्व सीबीआई कोर्ट में विवादित ढांचा गिराए जाने को लेकर कुल छह लोग कोर्ट में बयान दर्ज कराने पहुंचे, जिसमें रामविलास वेदांती, पवन पांडे, विनय कटियार, गांधी यादव, विजय बहादुर सिंह व संतोष दुबे शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि कोर्ट इस समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा ३१३ के तहत कार्यवाही कर रही है। इसके तहत अभियुक्तों को स्पष्टीकरण देने का मौका दिया जाएगा। साथ ही उनके खिलाफ सीबीआई की गवाही में आए उन तथ्यों पर भी उनको स्पष्टीकरण देने का मौका दिया जाएगा जो उनके खिलाफ हैं। विशेष जज एसके यादव ने बचाव पक्ष के वकीलों को पिछली सुनवाई के दौरान ही ताकीद की थी कि ४ जून से अभियुक्तों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इससे पूर्व कोर्ट ने सीबीआई की ओर से

प्रारम्भ कर दिया था। पहले अभियुक्तगणों चम्पत राय, लल्लू सिंह व प्रकाश शर्मा को २४ मार्च को बुलाया गया था। लेकिन लाकडाउन के कारण कोर्ट की कार्यवाही संपन्न नहीं हो सकी। १८ मई से केस की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई तो बचाव पक्ष ने तीन गवाहों की जिरह के लिए अर्जी दे दी। उस अर्जी का निस्तारण कर कोर्ट ने कार्यवाही समाप्त कर ली है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी ८ मई २०२० को एक आदेश जारी कर इस केस की सुनवाई ३१ अगस्त तक पूरी करने का निर्देश विशेष अदालत को दिया है। इसी वजह से विशेष अदालत केस की सुनवाई दिन प्रतिदिन कर रही है। केस में पूर्व डिप्टी पीएम एलके आडवाणी, बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी व उमा भारती को केस की कार्यवाही के समय व्यक्तिगत हाजिरी से अग्रिम आदेशों तक छूट है।

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री ने राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान का किया औचक निरीक्षण

लखनऊ। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान निशातगंज का बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ सतीश चन्द्र द्विवेदी ने गुरुवार

पहुंचे थे, निरीक्षण के बाद डॉ द्विवेदी ने बातचीत में बताया कि लैब से लेकर मशीनों के रख रखाव की स्थिति ठीक नहीं थी, साथ ही

संभव कदम उठाये जा रहे हैं, साथ ही सरकारी दफ्तरों में साफ-सफाई रखने के निर्देश हैं, यदि इस तरह गंदगी कहीं भी होगी तो कोविड-१९ को हरा पाना मुश्किल होगा। डॉ द्विवेदी ने कहा उनकी ओर से शिक्षा विभाग के सभी आफिसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ-साथ नियमित साफ सफाई के आदेश दिए गये हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभागों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो इसके लिए नियमित निरीक्षण भी किया जायेगा। साथ ही अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गयी है कि वह अनिवार्य रूप से विभाग में आने जाने वाले लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएँ, साथ ही विभाग में लोगों की भीड़ न लगने पाये इसका विशेष ध्यान रखें।



को औचक निरीक्षण किया। जहां उन्हें कई खामिया मिली तो उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए सुधार के निर्देश दिए। बेसिक शिक्षा मंत्री बिना किसी सूचना के अचानक

गंदगी के साथ-साथ ऐसा लग रहा था कि देख रेख में भी लापरवाही की जा रही है, जो कि सही नहीं था। बेसिक शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश में कोविड-१९ से बचाव के लिए सरकार की ओर से हर

चाचा शिवपाल के सामने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे : अखिलेश

लखनऊ। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि शिवपाल यादव के सामने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नहीं उतारेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में हर चुनौतियों का सामना करेगी, क्योंकि समाजवादियों की सरकार आगामी विधानसभा चुनाव पश्चात बनने जा रही है। विधानसभा चुनाव २०२२ में समाजवादी पार्टी किसी अन्य पार्टी से समझौता नहीं करेगी और अपने बूते पर फतह करेगी। इसकी वजह है कि प्रदेश की वर्तमान सरकार फेल हो चुकी है। मीडिया को जारी बयान में

अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों और श्रमिकों को



गुमराह करने के लिए घोषणाओं पर घोषणाएं कर रही है लेकिन उनका क्रियान्वयन कहीं दिख नहीं रहा। प्रधानमंत्री के एक भाषण से दूसरे भाषण तक उनकी सभी

जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं। उनकी आत्मनिर्भरता की बात में तो तनिक भी दम नहीं। यह उनके पांच साल पहले के तमाम वादों की कड़ी भर है। उनके मन की बात से तो यह लगता है कि हर कोई अब अपने जानमाल का खुद जिम्मेदार होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ दे दिया है। किसान और मजदूर दूढ़ रहे हैं कहां है क्या दिया है? अपने पांवों पर खड़े होने में आर्थिक मदद देने के बजाय उसे और कर्जदार बनने के की साजिश है।

मोदी ने मारवाह के निधन पर शोक व्यक्त किया

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त और मणिपुर, मिजोरम तथा



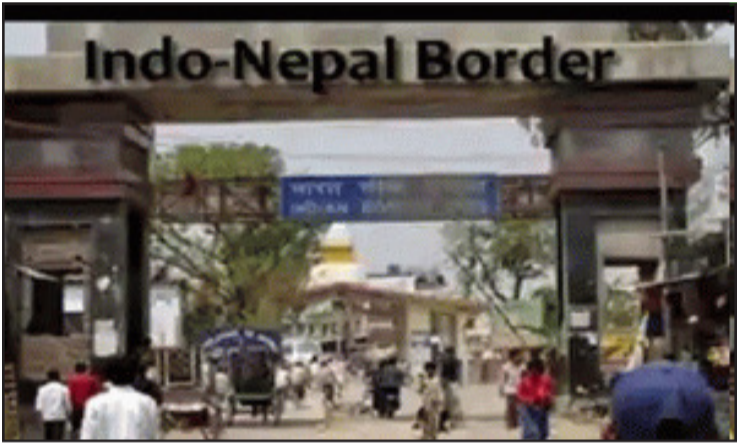
झारखंड के पूर्व राज्यपाल श्री वेद मारवाह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मोदी ने ट्विटर पर अपने शोक संदेश में कहा, श्री वेद मारवाह जी को सार्वजनिक जीवन

में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए याद किया जाएगा। एक आईपीएस अधिकारी के रूप में अटूट साहस हमेशा उनके जीवन में बना रहा। वह सम्मानित बुद्धिजीवी थे। उनके निधन से बहुत दुख हुआ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। मारवाह का शुक्रवार रात गोआ के एक अस्पताल में निधन हो गया था। वह ८७ वर्ष के थे। वह वर्ष १९८५ से १९८८ तक दिल्ली पुलिस आयुक्त के पद पर रहे थे।

भारत-नेपाल सीमा पर लोगों का आवागमन शुरू

बहराइच। नेपाल सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के बहराइच में लकडाउन के दौरान फंसे दोनों ओर फंसे नागरिकों का रुपईडीहा

नागरिकों का अपने देशों में आवागमन जारी है। एसएसबी के कमांडेंट प्रवीण कुमार ने बताया कि कल भारत के विभिन्न प्रदेशों



के रास्ते अपने देशों में आवागमन जारी है। नेपाल के काफी संख्या में श्रमिक भारत के विभिन्न प्रदेशों में मजदूरी कर रहे थे। वैश्विक महामारी को रोकने के लिए केंद्र सरकार को देश में लकडाउन की घोषणा करनी पड़ी। लकडाउन के चलते नेपाल के नागरिक भारत एवं भारत के नागरिक नेपाल में फंसे हुए थे। दोनों देश के सरकारों द्वारा कुछ ढील देने के बाद

में रहने वाले २०६८ नेपाली नागरिकों ने नेपाल में प्रवेश लिया जबकि नेपाल के ईट भट्टों पर काम करने वाले ३५० भारतीय नागरिक भारत में प्रवेश किया। कमांडेंट ने बताया कि सीमा पर सभी श्रमिकों की जांच की गई। इसके बाद सभी को वाहन पर बैठाया गया। इस दौरान पुलिस और एसएसबी के अधिकारी एवं जवान मौजूद रहे।

मोदी-योगी की पाती घर-घर लेकर जाएंगे भाजपा कार्यकर्ता

सुलतानपुर। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यकर्ता १० से १५ जून के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पाती लेकर घर-घर जायेंगे। भाजपा के जिला प्रवक्ता विजय सिंह रघुवंशी ने बताया कि संपर्क अभियान के अंतर्गत मण्डल, सेक्टर एवं बूथ स्तर के कार्यकर्ता १० जून से १५ जून के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पाती लेकर घर-घर जायेंगे। इस दौरान वे १०० घरों में संपर्क कर उनका नाम एवं मोबाइल नंबर भी एकत्रित करेंगे। जनप्रतिनिधि भी अपने मण्डल के किसी एक बूथ पर जाकर लोगों से संपर्क कर मोदी और योगी की

पाती देंगे। कल पिछड़ा वर्ग मोर्चा एवं १० जून को किसान, युवा एवं महिला मोर्चा की वर्चुअल रैली होगी। १६ जून से २२ जून तक क्षेत्रीय स्तर की वर्चुअल रैली होगी। उन्होंने बताया कि पार्टी लगातार मण्डलों की वर्चुअल बैठक आयोजित कर पार्टी नेतृत्व द्वारा तय किए गए आगामी जून माह कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को बूस्ट कर रही है। जिसके क्रम में शनिवार को सुलतानपुर के सुलतानपुर, कादीपुर, लंभुआ एवं सदर-जयसिंहपुर विधानसभा अंतर्गत के २१ मण्डलों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठके संपन्न की।

सरकार निर्बाध बिजली देने के लिए प्रयासरत : योगी

बस्ती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार सभी नागरिकों को निर्बाध ढंग से बिजली प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। योगी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से २६ करोड़ ३४ लाख रुपये की लागत से निर्मित १३२ केवीए विद्युत उपकेंद्र कलवारी का लखनऊ से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण करने के बाद कहा कि प्रदेश

सरकार सबको बिजली पर्याप्त बिजली और निर्बाध बिजली देने



के लिए प्रयासरत है। इस उपकेंद्र के चालू हो जाने के बाद महादेवा विधानसभा क्षेत्र समेत अन्य ग्रामीण

क्षेत्र में ३२००० ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं एवं लघु उद्योग को लाभ मिलेगा और बेहतर ढंग से 'अभी रुको' को बिजली की आपूर्ति मिल सकेगी। इस दौरान एनआईसी बस्ती में लोकसभा क्षेत्र बस्ती के संसद सदस्य हरीश द्विवेदी विधानसभा क्षेत्र महादेवा के विधायक रवि सोनकर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन के अलावा बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

खाता न बही जो पीएम कहे वो सही : अखिलेश

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पर तंज कसते हुये कहा कि भाजपा

रहा है। इसे भी भाजपा की अन्य जुमलेबाजी वाली योजनाओं की गिनती में क्यों न रखा जाये। उन्होंने

उनके जारी प्रेसनोट से नहीं। श्रमिकों के सामने गहरा अंधेरा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री केवल बयानों में रोजगार बांट रहे हैं। हवा में विदेशी कम्पनियों के उत्तर प्रदेश में आने की तुकबंदी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड-१९ संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या १० हजार से ऊपर

राज में खाता न बही जो पीएम कहे वही सही के तर्ज पर राजकाज चल रहा है। यादव ने कल कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट हों या समय-समय पर राहत पैकेजों की घोषणा सब में ब्यौरे गायब रहते हैं। भाजपा सरकार द्वारा घोषित २० लाख करोड़ के 'महा पैकेज' में कितना गरीब को मिलेगा, कितना किसान, दिहाड़ी कर्मियों, प्रवासी मजदूर, छोटे और खुदरा व्यापारी, ठेले-पटरी वाले और अन्य मजदूर लोगों में बंटना है, इसका कोई खुलासा नहीं कर



कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अपने नेता के पद चिन्हों पर चलते हुए नित नए आयोगों के गठन में व्यस्त हैं। पूरे प्रदेश में काम की आस में मजदूरों की आंखें पथरा रही हैं लेकिन सरकार को उनकी फिक्र नहीं। अब योगी बताये कि मेहनतकश का पेट रोटी से भरेगा आयोग की बैठकों और

पहुंच गई हैं। राजधानी लखनऊ में ही रोज नए केस मिल रहे हैं। भाजपा सरकार लॉकडाउन उठा रही है। अस्पतालों में इलाज के नाम पर या तो लूट हो रही है या लापरवाही। बच्चों के स्कूल कालेज बंद हैं। लॉकडाउन में आपूर्ति की पूरी चेन बिगड़ जाने से व्यापारी परेशान है।

शांति भंग में बंद नौ कांग्रेसियों को मिली जमानत

मथुरा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन देने के दौरान शांति भंग के आरोप में बंद नौ कांग्रेसियों को जिला जज की अदालत से जमानत मिलने के बाद रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आये कांग्रेस विधान मंडल दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर ने कहा कि योगी सरकार तानाशाही पर उत्तर आई है तथा उसके अधिकारी भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने लगे हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सरकार के किसी भी गलत कदम का विरोध करने का अधिकार हर राजनैतिक दल को होता है। उनका कहना था कि

कांग्रेसी जब अंग्रेजों के दमन के सामने नहीं झुकते तो योगी सरकार के सामने झुकने वाले नहीं हैं। उधर जेल से रिहा हुए कांग्रेस की मथुरा इकाई के अध्यक्ष दीपक चौधरी ने कहा कि जेल में बंद करने से कांग्रेसी डरनेवाले नहीं हैं। सरकार को कोरोना वायरस के संक्रमण का लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष को जेल में बंद कर दिया गया यदि कोरोना का संक्रमण काल न होता तो कांग्रेसी प्रदेश की जेलों को भर देते। उनका यह भी आरोप है कि प्रशासन ने कांग्रेसियों को अस्थाई जेल में ऐसी जगह रखा जहां कोरोना संक्रमित पूर्व में रखा गया था। गौरतलब है

कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए तीन जून को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन देने गए कांग्रेसियों की जिला प्रशासन के अधिकारियों से हुई गर्मा-गर्मी के बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष दीपक चौधरी, प्रदेश सचिव मुकेश धनगर, महानगर अध्यक्ष उमेश शर्मा, जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्षा नीलम कुलश्रेष्ठ और महानगर महिला कांग्रेस अध्यक्ष शालू अग्रवाल समेत नौ कांग्रेसियों को १५ सीआरपीसी में जेल भेज दिया गया था तथा उनकी जमानत की अर्जी अगले दिन सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय से खारिज कर दी गई थी।

अमरनाथ यात्रा: २१ जुलाई से शुरू होकर ३ अगस्त तक चलेगी

जम्मू। जम्मू-कश्मीर में इस साल की अमरनाथ यात्रा २१ जुलाई से शुरू होकर ३ अगस्त को तक चलेगी। यह १५ दिनों की अवधि की होगी। यह बात श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (एसएसबी) के अधिकारियों ने कही, जो जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में समुद्र तल से ३,८८० मीटर ऊपर स्थित गुफा मंदिर में यात्रा के मामलों का प्रबंधन करता है। यात्रा के लिए 'प्रथम पूजा' शुक्रवार को आयोजित की गई थी। कोरोनावायरस महामारी के कारण इस बार यात्रा की अवधि में कटौती की गई है। साधुओं को छोड़कर अन्य तीर्थयात्रियों में ५५ वर्ष से कम उम्र

के लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। यात्रा करने वाले सभी लोगों के पास कोविड निगेटिव प्रमाणपत्र होने चाहिए। एसएसबी के एक अधिकारी ने कहा, "तीर्थयात्रियों को जम्मू-कश्मीर में यात्रा शुरू करने की अनुमति देने से पहले उनको वायरस के लिए क्रस-चेक किया जाएगा। साधुओं को छोड़कर सभी तीर्थयात्रियों को यात्रा के लिए अनलाइन पंजीकरण करना होगा। यह भी तय किया गया है कि १५ दिनों के दौरान सुबह और शाम गुफा मंदिर में की जाने वाली 'आरती' का देश भर के भक्तों के लिए सीधा प्रसारण किया जाएगा। अधिकारियों

ने कहा कि स्थानीय मजदूरों की अनुपलब्धता और बेस कैंप से गुफा मंदिर तक ट्रैक बनाए रखने में कठिनाइयों के कारण, यात्रा २०२० के लिए गांदरबल जिले में बालटाल बेस कैंप से गुफा तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा। यात्रा २०२० केवल उत्तरी कश्मीर बालटाल मार्ग से होकर निकलेगी। अधिकारियों ने कहा, "इस वर्ष किसी भी तीर्थयात्री को पहलगाम मार्ग के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा २०२० का समापन ३ अगस्त को श्रावण पूर्णिमा पर होगा जिस दिन रक्षा बंधन का त्योहार होता है।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय की मीडिया टीम में हुआ बदलाव

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की मीडिया टीम पूरी तरह बदल दी गई है। अब भारतीय सूचना के वरिष्ठ अधिकारी नितिन डी. वाकणकर को नेतृत्व सौंपा गया है, और उनके अधीन एक नई टीम नियुक्त कर दी गई है। वाकणकर ने वसुधा गुप्ता की जगह ली है। बसुधा को जांच इकाई में महानिदेशक बनाया गया है। आधिकारिक बयान के अनुसार, वाकणकर महानिदेशक स्तर के अधिकारी हैं, और उन्हें पीआईबी के 'ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशंस' से

गृह मंत्रालय भेजा गया है। वाकणकर, १९८६ बैच के आईआईएस अधिकारी हैं। वह

जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, सूचना सेवा के अन्य अधिकारी राजकुमार को गृह मंत्रालय की मीडिया विंग में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उप निदेशक प्रवीण कवि को भी गृह मंत्रालय की मीडिया विंग में नियुक्त किया गया है। वह पहले भी इस मंत्रालय में सेवा दे चुके हैं। सहायक निदेशक अमनदीप यादव को भी मंत्रालय की मीडिया विंग में नियुक्त किया गया है।



पहले सीबीआई के प्रवक्ता रह चुके हैं। वह रक्षा मंत्रालय के भी प्रवक्ता रह चुके हैं और अपने करियर के दौरान उन्होंने मुंबई क्षेत्र में विभिन्न

२० लाख करोड़ के पैकेज में गरीबों के लिए

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार द्वारा दिये जा रहे पैकेज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि २० लाख करोड़ के पैकेज में गरीबों के लिए कितना है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को ट्वीटर के माध्यम कहा, सरकार बस इतना बता दे कि २० लाख करोड़ के तथाकथित 'महापैकेज' में कितना गरीब के

लिए है कितना किसान, दिहाड़ी-प्रवासी मजदूर, छोटे व्यापारी, खुदरा कारोबारी,



रेड़ी-ठेले-पटरीवाले व अन्य मजदूरों के लिए है। समाज को बांटने में माहिर लोग पया करके

कितना है : अखिलेश

इस आर्थिक बंटवारे का हिसाब भी दे दें। इससे पहले उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा था, बाराबंकी से एक परिवार के पांच लोगों के अलावा उग्र के अन्य शहरों से भी आत्महत्याओं की दुखद खबरें आ रही हैं। भाजपा सरकार से अपेक्षा है कि तत्काल लोगों के खाने और कमाने का इंतजाम करे। सबसे पहले प्रदेश में भूख से लोगों का मरना रुकना चाहिए।

स्कूलों को सुरक्षा उपायों के साथ खोलना बेहतर कदम : सिसोदिया

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर कुछ बड़े प्रयोगों करने पर सुझाव दिया है। सिसोदिया ने देश में स्कूलों को फिर से खोलने से पहले कई गंभीर विषयों पर रचनात्मक और साहसिक तरीकों से विचार करने पर बल देते हुए लिखा, कोरोना के बाद अब पुराने तरीके से पढ़ाई नहीं चल सकती। अब शिक्षा में बड़े बदलाव की जरूरत है। ऐसे बदलाव के लिए हम खुद आगे बढ़कर पहल करें, न कि विदेशों में कोई नई चीज होने का इंतजार करें और फिर उसकी नकल करें। मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में कहा,

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ समय पहले कहा था कि हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी।



ऐसे में स्कूलों को उचित सुरक्षा उपायों के साथ खोलना ही बेहतर कदम होगा। सिसोदिया ने लिखा है कि सबसे पहले, हमें हर बच्चे को भरोसा दिलाना होगा कि वह हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। अपने स्कूल के भौतिक और बौद्धिक परिवेश पर सबका समान अधिकार

है। केवल अनलाइन क्लास से शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती। केवल बड़े बच्चों को स्कूल बुलाना और छोटे बच्चों को अभी घर में ही रखने से भी शिक्षा को आगे बढ़ाना असंभव होगा। पत्र के अनुसार, अनलाइन शिक्षा को स्कूल में सीखने की प्रक्रिया की एक पूरक व्यवस्था के तौर पर देखा जाना चाहिए। यह उसका विकल्प नहीं हो सकती। स्कूलों को खोलने के लिए जो भी दिशा-निर्देश जारी हों, उसमें हर उम्र और हर वर्ग के बच्चे को बराबर अवसर देना होगा। यह ध्यान रखा जाए कि हमारा अगला कदम बड़े बच्चों को छोटे बच्चों के ऊपर प्राथमिकता देने के पूर्वाग्रहों पर आधारित न हो।

कोविड-१९ : पाकिस्तान में बेरोजगार होंगे ३० लाख लोग

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय ने कहा कि कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर देश में औद्योगिक और सर्विस सेक्टर से जुड़े अनुमानित ३० लाख (३ मिलियन) लोगों की नौकरी जा सकती है और गरीबी का स्तर मौजूदा २४.३ प्रतिशत से बढ़कर ३३.५ प्रतिशत हो सकता है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के उच्च सदन सीनेट को मंत्रालय ने शुक्रवार को सूचित कर कहा, "सर्विस सेक्टर में २० लाख (२ मिलियन) से अधिक नौकरियों के जाने की संभावना

है, जबकि महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट पर औद्योगिक क्षेत्र में १० लाख (एक मिलियन)



नौकरियां जाएंगी। समाचार एजेंसी ने मिनिस्ट्री के हवाले से कहा, महामारी से पहले सकल घरेलू

उत्पाद की वृद्धि दर ३.२४ प्रतिशत होने की उम्मीद थी, जो अब चालू वित्त वर्ष के दौरान घटकर -०.४ प्रतिशत हो गई है। इसने यह भी कहा कि राजकोषीय घाटा भी जीडीपी के शुरुआती लक्ष्य ७.५ प्रतिशत से बढ़कर ६.४ प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में अब तक ८६ हजार २४६ लोग कोरोनावायरस महामारी से संक्रमित हुए हैं। जबकि देश में कोविड-१९ संक्रमण की चपेट में आकर १ हजार ८३८ लोगों ने अपनी जान गंवाई है।

'आयुष कवच' एप से घर बैठे मिल रही डॉक्टरी सलाह

लखनऊ। आयुष मिशन ने अपने एप 'आयुष कवच' के माध्यम से मरीजों को घर बैठे इलाज की सुविधा प्रदान करनी शुरू कर दी है। एप के माध्यम से फोन करके आयुर्वेद, यूनानी व होम्योपैथी विशेषज्ञों से बीमारियों से बचाव लिए सलाह ली जा सकती है। आयुष मिशन निदेशक राजकमल ने बताया, इसमें तीनों विधाओं के करीब २३० डॉक्टर सुबह आठ बजे रात आठ बजे तक सलाह दे रहे हैं। तीन दिनों में १००० से अधिक लोगों ने जानकारी ली है। इस एप पर एक बार में १०० से १५० कल रिसीव की जा सकती है। मिशन निदेशक ने बताया, आयुष विधा में लोगों की बढ़ती रुचि को देखते हुए दो जून को इसमें विशेष फीचर टेली परामर्श का जोड़ा गया है। इसे आयुष टेली कवच का नाम दिया गया है। उन्होंने बताया, एप के माध्यम से फोन कल पर

डॉक्टर मरीज या उसके परिजन से बात कर बीमारी के लक्षण या अन्य जिज्ञासाओं के उत्तर देते हैं। इसके अलावा एप पर आयुष संवाद



कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। हर शाम पांच बजे से एप पर लाइव कार्यक्रम चलता है। राजकमल ने बताया कि इस एप में तमाम ऐसी सुविधाएं हैं, जो लोगों के लिए काफी उपयोगी हैं। कोविड-१९ से बचने के उपाय, लाइव योग, रोग प्रतिरोधक बढ़ाने की क्षमता के उपाय, मुख्यमंत्री राहत कोष कोविड केयर फंड में योगदान व राज्यस्तरीय कंट्रोल की जानकारी दी गई है।

रेलमंत्री पीयूष गोयल की मां चंद्रकांता गोयल का निधन

मुंबई। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता व रेलमंत्री पीयूष गोयल की मां चंद्रकांता गोयल का आज सुबह यहां निधन हो गया। वह ८८ साल की थीं। गोयल ने अपनी

भी सेवाभाव से जीवन बिताने को प्रेरित किया। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति। मुंबई के माटुंगा से ३ बार विधायक रह चुकीं चंद्रकांता गोयल वरिष्ठ



मां के निधन की जानकारी एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी, जो काफी भावुक करने वाला था। गोयल ने ट्वीट में कहा, अपने स्नेह और प्रेम से मुझे हमेशा राह दिखाने वाली मेरी पूज्य माता जी का आज सुबह स्वर्गवास हो गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन सेवा करते हुए बिताया और हमें

भाजपा नेता दिवंगत वेद प्रकाश गोयल की पत्नी थीं। वेद प्रकाश गोयल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में शिपिंग मंत्री थे। गोयल परिवार लंबे समय से जनसंघ और भाजपा से जुड़ा हुआ है और उनके बेटे पीयूष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में रेल मंत्री हैं।

ओटीएस योजना की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ी

लखनऊ। प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने ओटीएस योजना की तिथि ३० सितंबर तक बढ़ा दी है। इसका आदेश जारी हो गया है। इससे आवास विकास एवं प्राधिकरणों के आवंटियों को राहत मिली है। योजना ५ जून को समाप्त हो गई थी। प्रदेश सरकार ने आवास विकास एवं प्राधिकरणों के डिफाल्टर आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना ६ मार्च २०२० से तीन महीने के लिए लागू की थी, जो ५ जून को समाप्त हो गयी है। योजना के तहत

डिफाल्टर आवंटियों को चक्रवृद्धि ब्याज में छूट मिलेगी। देश में लॉक डाउन के चलते आवास विकास सहित विकास प्राधिकरणों के कार्यालय बंद रहे, जिससे आवंटी योजना का लाभ नहीं उठा पाये थे। केवल ऑनलाइन आवेदन ही आए थे। अधिक से अधिक लोगों को योजना का लाभ देने के लिए प्रमुख सचिव आवास ने ३० सितंबर तक योजना की तिथि बढ़ा दी है। योजना के तहत आवंटी अब ३० सितंबर तक आवेदन फार्म जमा कर सकेंगे।

रवि गुप्ता ने एकता कपूर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर एकता कपूर का पुतला फूंक जताया विरोध

पलिया कलां खीरी। समाजसेवी रवि गुप्ता ने मुंबई निवासी डायरेक्टर व अभिनेत्री एकता कपूर का पुतला फूंक कर पलिया के कोतवाल श्री विद्या शंकर शुक्ला जी एवं सीओ श्री राकेश नायक जी को लिखित तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने देश के गद्दारों के खिलाफ आज पुलिस में शिकायत करवाई है। देश की ये गद्दार निर्माता एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर हैं। आखिर वो क्या मामला है जिसके कारण समाज सेवी रवि गुप्ता ने इन दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। आपको बता दें कि आज से लगभग 5 साल पहले 2015 में एकता कपूर

के अल्ट बालाजी द्वारा एक वेब सीरीज बनाई गयी थी जिसका नाम गगन था। इस वेब सीरीज में इंडियन आर्मी को लेकर एक आपत्तिजनक सीन दिखाया गया था। जिसके लेकर उस समय भी लोगों से विरोध जताया था लेकिन कोई शिकायत नहीं दर्ज की गयी थी। रवि ने इसके खिलाफ अवाज उठाई है और एकता कपूर और उनकी मां के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की मांग कर पुतला फूंक कर विरोध जताया है। फिल्म में दिखाया गया है कि एक औरत का पति फौज में होता है इसी लिए वह ड्यूटी पर चला जाता है जिसके बाद फौजी की पत्नी का किसी और के साथ अफेयर

हो जाता है। इस दौरान काफी इटिमेंट सीन वेब सीरीज में दिखाई गये हैं एक सीन में इंडियन आर्मी की वर्दी में सीन दिखाया गया है जो काफी आपत्तिजनक और अश्लील था। इस सीन को लेकर बवाल मचा है। रवि ने थाने में शिकायत की है कि ये भारतीय सेना की वर्दी का अपमान है। जिसके खिलाफ पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद करने की गंभीर साजिश है इसलिए इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और जेल भेजा जाए साथ ही रवि गुप्ता ने जूतों की माला पहनाकर एकता कपूर का पुतला भी फूँका है।

पक्षपाती वाहन चेकिंग का विरोध सपा के

मोहम्मदी-खीरी। वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस के पक्षपात पूर्ण रवैये का विरोध करने पर पुलिस ने क्षेत्र के सम्मानित एवं सपा नेता जो एक डिग्री कालेज सहित कई शिक्षण संस्थाओं के संचालक है सहित तीन लोगों को रामलीला चौराहे से कोतवाली तक बेत चलाते एवं गालियां देने की गूँज मोहम्मदी से निकल कर जिला मुख्यालय और प्रदेश की राजधानी तक पहुँच गयी। विधि संगत कार्यवाही न होने पर पीड़ित निचली अदालत से लेकर

उच्च न्यायालय तक जा सकते हैं। नगर के रामलीला मैदान में रहने वाले तथा पसगवां सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात एक संविदा चिकित्सा अधिकारी का पुत्र बीती शाम रोडवेज के पास आया था। वापस जाते समय रामलीला गेट के पास हो रही वाहन चेकिंग में फंस गया। मौके पर सिर्फ उसके पास डीएल नहीं था। "साहब" ने खाकी की हनक में डीएल मांगा तो उसने अपने पापा, चाचा को फोन किया कि घर से डीएल भिजवा दे।

चाचा भतीजा को पड़ा

इत्तिफाक से चाचा डिग्री कालेज से वापस आ रहे थे चौराहे पर रुक गए। उनके सामने कई बाइक जिन पर तीन-तीन लोग सवार थे लेकिन वो सत्ता पक्ष से जुड़े होने के कारण पुलिस ने उनको नहीं रोका। इसी बात पर भइया के चाचा और साहब के बीच पक्षपात पूर्ण रवैये पर विवाद होने लगा। चाचा का कहना था कि नियम सबके लिये समान होना चाहिये। कहावत है कि सच बात कड़वी होती है। ये कड़वी बात "साहब" को नागवार लगी और

युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए उपलब्ध करवाया जायेगा ऋण

लखीमपुर-खीरी। आत्मनिर्भर भारत को लेकर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास सामने आया है। अनुसूचित जाति के बेरोजगारों को रोजगार शुरू करने के लिए अनुदान ऋण दिलाया जायेगा। इसके लिए योजनायें चलाई जा रही हैं। इसमें स्वरोजगार, दुकान निर्माण योजना, टेलरिंग शॉप आदि शामिल है। आवेदन करके युवा रोजगार शुरू कर सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति के ऐसे बेरोजगारों के लिए जिनकी ग्रामीण क्षेत्र में आय 86000 और शहरी क्षेत्र में आय 56800 है। उनको स्वरोजगार के लिए योजनायें चलाई जा रही हैं। 95

जून तक आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि स्वतः रोजगार योजना में बैंक के माध्यम से परियोजना लागत 50 प्रतिशत या 90000 जो भी कम हो अनुदान के रूप में दिया जाता है। 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए अलावा नगरी क्षेत्र के युवाओं के लिए दुकान निर्माण योजना चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि परिवारिक लाभ योजना का लाभ लेने जाति की पात्र महिलाएं और कौशल विकास से सांलिई, कढ़ाई में ट्रेड महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। जाति आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के साथ आधार लगाकर अपना आवेदन करें। खुद का रोजगार शुरू करें और आत्म निर्भर बन सकें।

अद्भुत अंडा : हरे रंग की जर्दी वाला अंडा

अमरेन्द्र सहाय अमर सन्डे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। यह प्रचार टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर एक समय में खूब चला था। अंडे में भरपूर पौष्टिक तत्व होता है, जो सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। अंडे को उबालकर खाएं या पकाकर खाएं इसका सेवन हर तरफ से फायदेमंद होता है। हालाँकि शाकाहारी लोग अंडे नहीं खाते, मैं उन्हें इसके सेवन की सलाह भी नहीं दे रहा हूँ, कुछ लोग अंडे को सुपरफूड भी मानते हैं। खासतौर पर अंडे की जर्दी काफी पौष्टिक और जायकेदार होती है। यह भी आप जानते होंगे कि अंडे देशी और फार्म वाले होते हैं। देशी अंडे की जर्दी कुछ पीले रंग की परन्तु फार्म के अंडे की जर्दी बिलकुल सफेद होती है। अगर हम कहें कि अंडे की जर्दी हरे रंग की होती है तो आप सहसा विश्वास नहीं करेंगे और आप कहेंगे मैं फेंक रहा हूँ, हालाँकि मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरे कथन के प्रमाण में आप आप फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, जिसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है। दरअसल केरल के मल्लपुरम के कोट्टाकल स्थित शहाबुद्दीन पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां जो अंडे दे रही हैं, वे बाहर से देखने में तो सामान्य

होते हैं लेकिन जब उन्हें फोड़ा जाता है उन अण्डों की जर्दी सफेद या पीलापन लिए न होकर हरे रंग की होती है। इस पोल्ट्री फार्म के मालिक शहाबुद्दीन का कहना है कि उनका पूरा परिवार हरे रंग

अगर कुछ अलग हो तो देखा जा सके। लेकिन इसमें कुछ अलग नहीं दिखा था। चूजे बिलकुल सामान्य थे। शहाबुद्दीन का मानना है कि ऐसा पोल्ट्री में मुर्गियों को दिए जाने वाले खानपान के

यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक ने जांच के बाद कहा मुर्गियों की खानपान की वजह से जर्दी का रंग हरे रंग का हो रहा है। उन्होंने अपनी जांच में पाया कि जब मुर्गियों को मिलने वाले खाने की

की जर्दी हरे रंग की हो जाती है। दरअसल केरल में मुर्गियों को आम तौर पर कुरुनथोटी नाम के पौधे से बना चारा दिया जाता है। इस पौधे के कारण ही जर्दी हरे रंग की हो जाती थी। वैज्ञानिक



की जर्दी वाला अंडा सेवन कर रहा है। शहाबुद्दीन ने जब इन अण्डों को सोशल मीडिया पर डाला तो यह तेजी से वायरल हो गया क्योंकि यह अद्भुत अंडा था। इसके बाद फार्म के मालिक शहाबुद्दीन ने कुछ अण्डों से चूजे निकलने का इंतजार किया, ताकि

कारण हो सकता है। उनके फार्म में कई प्रजातियों की मुर्गी हैं। उनका यह भी मानना है कि क्रस ब्रीडिंग के कारण भी ऐसा हो सकता है। हालाँकि विशेषज्ञ इसकी वैज्ञानिक जांच की मांग करने लगे। इसके बाद इन अण्डों को लेकर केरल के एक एनीमल साइंस

जाँच की तो जर्दी के हरे रंग के होने का खुलासा हो गया। दरअसल इन मुर्गियों को खिलाया जाने वाला चारा ही हरे रंग का था। वैज्ञानिक ने खुलासा किया कि जब मुर्गियों को मिलने मिलने वाले चारे में अधिक भाग हरे रंग का हो, तब ऐसा होता है कि अंडे

ने इन मुर्गियों के चारे में बदलाव किया तो अंडे की जर्दी सामने अंग की हो गयी। इस घटना को कोरोना से जोड़ते हुए अपनी ट्वीट में कवि कुमार विश्वास ने लिखा कि मुर्गियों तक समझ रही हैं कि ग्रीन जोन जीना जरूरी है, यह पट्टे कब तक समझेंगे।

कोरोना चेन को तोड़ने के लिए सावधानी व सतर्कता बरतना आवश्यक : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-१९ के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी व सतर्कता बरती जाय। सीएम योगी ने शुक्रवार को अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी सावधानी व सतर्कता बरतना आवश्यक है। सभी स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाय। पुलिस द्वारा प्रभावी पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी भीड़ एकत्र न होने पाए। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन सेंटर तथा कम्युनिटी किचन को संचालन की स्थिति में रखा जाए। क्वारंटीन सेंटर तथा कम्युनिटी किचन को सेनिटाइज करके रखा जाए, ताकि आवश्यकतानुसार इनका उपयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कामगारों/श्रमिकों को राशन किट तथा एक हजार रुपए का भरण-पोषण भत्ता दिया जाए। उन्होंने

कहा कि सभी व्यवस्थाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाय। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों से प्रतिदिन सीधे संवाद कर कोविड चिकित्सालयों की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखें। उन्होंने कहा कि



अस्पतालों में रोगियों को पीने के लिए गुणगुना पानी उपलब्ध कराया जाए। एल-१ कोविड अस्पतालों में अक्सीजन तथा एल-२ श्रेणी के कोविड चिकित्सालयों में अक्सीजन तथा वेन्टिलेटर की व्यवस्था अवश्य हो। सीएम योगी ने कहा कि चिकित्सालयों में साफ-सफाई की बेहतर व्यवस्था की जाय। बेड शीट आदि नियमित रूप से बदली जाए। डॉक्टरों तथा नर्सिंग स्टाफ द्वारा नियमित राउण्ड लिया जाए। रोगियों को शुद्ध एवं सुपाच्य भोजन

उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने संक्रमित मरीजों की रिकवरी की गति तथा दर को बढ़ाने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के साथ-साथ जागरूकता तथा सर्विलांस की मदद से राज्य को संचारी रोग से होने वाली मृत्यु की दर में गिरावट लाने में सफलता मिली है। कोविड-१९ के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोग इसके बचाव के सम्बन्ध में जागरूक तथा सजग रहें। सीएम योगी ने निगरानी समितियों को सक्रिय रखते हुए सर्विलांस सिस्टम को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर से निरन्तर संवाद बनाए रखकर इन्हें प्रोत्साहित किया जाए।

चारबाग बस डिपो में तैनात कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के चारबाग बस डिपो में तैनात कर्मचारी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया। सहायक



यातायात निरीक्षक पद के तैनात आरएन गुप्ता आलमबाग बस टर्मिनल पर लगातार ड्यूटी कर रहे थे। इसके पहले इनकी ड्यूटी श्रमिकों को बसों से भेजने के लिए चारबाग रेलवे स्टेशन और शकुंतला मिश्रा विवि में लगाई गई थी। रोडवेज कर्मियों ने बताया कि गुरुवार की शाम आलमबाग बस टर्मिनल से ड्यूटी करके आरएन गुप्ता अपने घर गए। वहीं शुक्रवार को इनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव

निकली तो बस अड्डे पर तैनात अन्य कर्मचारी सहम गए। आनन-फानन में इसकी सूचना चारबाग डिपो के एआरएम अमरनाथ सहाय को दी गई। एआरएम ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी बीच में दो दिन की छुट्टी लेकर गया था। जहां उसने आरएमएल पौथालजी में जांच कराया। शुक्रवार को रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस मामले में सीएमओ को पत्र भेजकर अन्य कर्मियों की जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आलमबाग बस टर्मिनल को सेनेटाइज कराने के लिए प्रबंध को अवगत कराया है।

सलमान ने पर्यावरण दिवस पर पनवेल फार्महाउस की सफाई की

मुंबई। लॉकडाउन शुरू होने के बाद पनवेल स्थित अपने फार्महाउस पर वक्त बिता रहे सुपरस्टार सलमान खान ने हाल ही में स्वच्छ



भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को अभिनेता ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें

वह कथित गर्लफ्रेंड लूलिया वंतूर के साथ फार्महाउस के परिसर में सफाई करते हुए नजर आए। परिसर में गिरी हुई पत्तियों को इकट्ठा करने से लेकर गीली सड़कों पर झाड़ू लगाने तक सलमान ने खुशी-खुशी अपने कर्मचारियों के साथ फार्महाउस की सफाई करने में मदद की। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, हैशटैगस्वच्छभारत हैशटैगवर्ल्डइन्वारनमेंटडे। ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि सलमान खान का फार्महाउस निसर्ग चक्रवात से प्रभावित हुआ है। वहीं फिल्मों की बात करें तो सलमान अब फिल्म 'राधे' में दिखाई देंगे। दिशा पटानी के साथ इस एक्शन ड्रामा फिल्म के इस साल ईद पर रिलीज होने की उम्मीद थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसमें देरी हुई है।

जर्नलिस्ट का किरदार निभाएंगे शाहरुख

मुंबई। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान सिल्वर स्क्रीन पर जर्नलिस्ट का किरदार निभाते नजर आ सकते हैं। शाहरुख खान लंबे अरसे से फिल्मों से दूर हैं। वह अंतिम बार दिसंबर २०१८ में फिल्म 'जीरो' में दिखाई दिए थे। उसके बाद से शाहरुख ने न तो कोई फिल्म साइन की है और न ही इसकी कोई घोषणा की है। माना



जा रहा था कि वह राकेश शर्मा की बायपिक 'सारे जहां से अच्छा' में काम करेंगे लेकिन बाद में उन्होंने इसमें काम करने से इंकार कर दिया। बताया जा रहा है कि शाहरुख ने अयान मुखर्जी की फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में एक छोटे से किरदार के लिए शूट किया है। फिल्म में रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन

मुख्य भूमिकाओं में हैं। इसके अलावा शाहरुख ने आर. माधवन की फिल्म 'रॉकेटरी' में भी एक छोटे से किरदार के लिए शूट किया है। यह फिल्म इसरो के मशहूर रॉकेट साइंटिस्ट नाम्बी नारायणन की बायपिक है। शाहरुख ने इन दोनों किरदारों के लिए पिछले साल ही शूट किया है। बताया जा रहा है कि शाहरुख ब्रह्मास्त्र में एक साइंटिस्ट के किरदार

में दिखेंगे जो दर्शकों को फैंटेसी वर्ल्ड से रूबरू कराता है। वहीं, फिल्म 'रॉकेटरी' में शाहरुख एक जर्नलिस्ट के किरदार में दिखेंगे, जो नाम्बी नारायणन का इंटरव्यू करता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। फिल्म में माधवन भी एक नासा साइंटिस्ट के छोटे से किरदार में दिखेंगे।

मुंबई को मिस कर रही है सनी लियोनी

मुंबई। बॉलीवुड की बॉल्ड अभिनेत्री सनी लियोनी मुंबई को मिस कर रही है और भारत वापस आना चाहती है। सनी लॉकडाउन के बीच में ही अपने पति और बच्चों के साथ मुंबई से यूएस निकल गई थीं। उनका कहना था कि वो अपने बच्चों की सुरक्षा चाहती थीं। लेकिन अब एक बार फिर वो भारत वापस लौटना चाहती हैं। सनी अपने मुंबई के घर को बेहद मिस कर रही हैं और वो उसे छोड़कर बेहद दुखी भी हैं। सनी ने बताया कि जल्द से जल्द

फ्लाइट से अपने पति और बच्चों के साथ वापस भारत आना चाहती हैं। इसके अलावा सनी ने लॉकडाउन के बीच भारत से यूएस जाने का कारण भी बताया। सनी लियोनी ने यूएस पहुंचकर अपने बच्चों के साथ गार्डन की तस्वीर साझा की थी। जिसमें सनी लियोनी अपने बच्चों के साथ काफी खुश दिखाई दे रही थीं। सनी अक्सर अपनी फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं। फैंस उनकी हर पोस्ट को खूब पसंद भी करते हैं।

सुष्मिता की वेबसीरीज आर्या का ट्रेलर रिलीज

मुंबई। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन की आने वाली वेबसीरीज आर्या का ट्रेलर रिलीज हो गया है। सुष्मिता सेन वेबसीरीज से एक्टिंग की दूसरी पारी खेलने जा रही हैं। यह सीरीज डिज्नी-हॉटस्टार पर १६ जून को रिलीज की जाएगी। सुष्मिता की इस नई वेबसीरीज का निर्देशन राम माधवानी कर रहे हैं। वेबसीरीज का ट्रेलर देखने से पता लगता है कि इसकी कहानी परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है। आर्या अपने पति और तीन बच्चों के साथ रहती है, लेकिन अचानक ही उनकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है। आर्या के पति

हत्या कर दी जाती है, पति की हत्या होने के बाद आर्या अपने बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा उठाती है और खुद जुर्म की दुनिया में उतर जाती है। सुष्मिता सेन ने अपने रोल के बारे में बताया कि आर्या ताकत, दृढ़ संकल्प और अपराध से भरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि, खासतौर पर उनके लिए इसकी कहानी परिवार, धोखे और एक ऐसी मां की कहानी है जो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सुष्मिता सेन ने बताया कि उन्हें इस तरह का किरदार पाने में दशक लग गए और अब वह इस कहानी का हिस्सा बनकर बेहद खुश हैं।

हमारे अन्य प्रतिनिधि

संजय बाजपेई

सीतापुर

मो.9935160370

प्रियंका त्रिपाठी

नई दिल्ली

विधिक सलाहकार

सुरेश नारायण मिश्र

क्षेत्रीय सम्पादक

सौरभ कुमार, बिहार

मो.09386075289

मो० अरशद

ब्यूरो चीफ

मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा साईं आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन

भातखण्डे संगीत

महाविद्यालय के पीछे,

कैसरबाग लखनऊ से

छपवाकर एमआईजी

2/379 रश्मिखंड

शारदानगर आशियाना

लखनऊ उ०प्र० से

प्रकाशित।

आर.एन.आई

UPHIN/2010/32566

सम्पादक

आरती पाण्डेय

मो.9415087228

9889745884. 9807059191.

9026560178

Email-

adbhutsamachar

@yahoo.in

adbhut_samachar

@rediffmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक